the locally registered employees of the State in all the Public Sector industries; and

(b) the steps taken by Government to solve the unemployment problem of the Starte?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) No, Sir.

(b) The question of solving unemployment problem of the Mysore State, is a part of the problem of unemployment in the country. Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation with the full cooperation of Ministries incharge of industries are taking all feasible steps to solve this problem.

संकटप्रस्त कपडा मिलें

- 352. श्री ओम प्रकाश स्थागी : क्या बाजिक्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या देश में असफल और संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को खरीदने का सरकार का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) यदि नहीं, तो उन्हें बन्द होने से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में, उप-मंत्री (श्री मृहम्मद राफ्नी कुरेशी): (क) जी, नहीं । उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अपने अधीन ली गई, अथवा ली जाने वाली मिलों के परि-समापन अथवा पुनःस्थापन के प्रम्न पर ही सूती कपड़ा समवाय (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा परिसमापन अथवा पुनःस्थापन) अधिनियम 1967 की धाराओं के उपबन्धों के अनुसार विचार किया जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

्र (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है - जिसमें सूती कपड़ा मितों को सहायता देने लिये अब तक की गई कार्यवाही का ब्योरा दिया गया है। [पुस्तकालय में रख दिया । देखिय संख्या LT--2061/68]। आगे की कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है।

इम्पीरियल तम्बाक् कम्पनी

- 353. श्री जोम प्रकाश त्यागी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड ने अपने सिग्नेटों के मार्कों में से एक मार्के का नाम 'इंडिया किग्म' रखा है;
- (ख) यदि हां तो क्या 'इंडिया' शब्द के प्रयोगः पर प्रतिवन्ध लगाने का सरकार का विचार है जैसा कि राप्ट्रीय नेताओं के नामों के प्रयोग के मामले में किया गया है; और
- (τ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री विनेश सिंह): (क) सरकार को इस बात की जानकारी है।

(ख) और (ग). यदि इस णब्द का दुरूप-योग किया जायेगा तो प्रतिबंध लगाने के प्रकृत, पर विचार किया जायेगा।

DEVELOPMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES

- 354. SHRIMATI SAVITRI SHYAM: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY APPAIRS be pleased to state:
- (a) whether the outlay of Rs. 250 crores proposed for the development of small scale industries will be distributed to the States on the basis of population;
- (b) if so, whether the unemployment situation prevailing in Uttar Pradesh will also be taken into consideration; and
- (c) what incentives are being considered to encourage private entrepreneurs and institutional finance to make the resources available for the development of small scale industries?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL AND DEVELOPMENT COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) and (b). According to the Programme of Work for the Fourth Plan prepared by Small Scale Industries Development Organisation, the proposed outlay on small scale industries would be about Rs. 236 crores and not Rs. 250 crores. Of this, the allocation for small scale industries and industrial estates under the State Governments Schemes amounts to Rs. 145 crores and Rs. 20 crores respectively. Another Rs. 70.44 crores is proposed to be spent on Central Schemes, (These figures are from the draft Plan and may undergo changes during finalisation). No amount is allocated to the States on the basis of population; it is on the basis of the Schemes included in their draft plans which are discussed with the Planning Commission, Ministry of Industrial Development & Company Affairs, etc. However, the State Governments generally do take into consideration the unemployment situation in their respective programme during the plan period.

(c) Private entrepreneurs are being given various incentives for setting up small scale These include technical assistindustries. ance, financial assistance, supply of machinery on hire-purchase basis, facilities, supply of scare/imported materials. Government and financial institutions have introduced various schemes to assist small scale industries for obtaining credit facilities. Loans on liberal terms to these units including industrial co-operatives are available under the State Aid to Industries Act administered by the State Directors of Industries. Medium-term loans are available from the State Financial Corporations and the State Bank, The State Bank of India provides credit facilities for working capital, etc. A scheme for guaranteeing commercial banks loans to small scale industrial units known as Credit Guarantee Scheme is in operation by the Reserve Bank of India since 1st July, 1960.

रेलवे विभाग के बारे में शिकायतें और

सुशाव

355. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

ं (क) क्या यह सच है कि आम लोग रैलवे अधिकारियों को रेलवे विभाग के बारे में अपनी शिकायतें और सुझाव नहीं भेज सकते हैं क्योंकि वे नियमों को नहीं जानते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर कोई ऐसी व्यवस्था करने का सरकार का विचार है जिससे जन साधारण अपने विचारों को सरकार के समक्ष रख सकें?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसी व्यवस्था पहले से की जा चुकी है जैसा कि संलग्न विवरण में बनाया गया है।

विवरण

- 1. रेलवे स्टेशनों पर सहायक मास्टर के कार्यालय में स्पष्ट स्थान पर शिकायत पुस्तकें रखी गयी है जिसमें बिना कठिनाई के लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। यह उल्लेख-नीय है कि समुचित स्थान पर और तीसरे और ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालयों में तथा प्लेटफामों पर इस आशय के सूचना-पट्टे लगाये गये हैं कि शिकायत-पुस्तकें कहां रखी हैं। जिन स्थानों पर वास्तव में शिकायत पुस्तकें रखी गयी हैं, वहां उपयुक्त संकेत-पट्टे भी लगाये गये हैं।
- 2. शिकायत की पुस्तकें भोजन यान सहित खान-पान स्थापनाओं में, उन माल और पार्सल घरों में जहां ये स्टेशन की मुख्य इमारत से कुछ दूरी पर स्थित हैं और सभी सवारी गाडियों के गार्ड के पास भी रखी जाती हैं।
- उसके अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों पर "सुझाव और शिकायत पटियां" भी रखी गयी हैं:—
 - (1) महत्वपूर्ण स्टेशनों के प्लेटफार्मी पर,
 - (2) सवारी ले जाने वाली गाड़ियों के गार्ड के डिब्बे में; और
 - (3) चुने हुए रेस्तोरां, भोजनालयों और रेस्तोरां/भोजन यानों में।